

Title: Regarding water crises and electricity tariff

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, पिछले काफी समय से दिल्ली में पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही बिजली की प्राबल्य बढ़ गई है। (व्यवधान) दिल्ली में पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिये सरकार की तरफ से 3-4 महीने पहले तैयारी होनी चाहिये थी लेकिन वह दिल्ली की सरकार ने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली में पानी और बिजली का जो संकट है, वह दिल्ली सरकार की भ्रष्ट, अपराधपूर्ण लापरवाही का परिणाम है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज आपने अखबारों में देखा होगा। (व्यवधान) आज अखबारों में फोटो छपी है कि पानीपत के पास मुनक नहर का दिल्ली की मुख्य मंत्री ने उद्घाटन किया है। जब मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री था तब 12 जून, 1994 को यमुना नहर पानी का समझौता हुआ था। उसके पहले हम हरियाणा से पानी खरीदते थे, लेकिन हमारी सरकार ने दिल्ली में आने के छः महीने के भीतर दिल्ली को उस पानी का भागीदार बनाया था। उस फैसले में यह व्यवस्था थी कि मुनक नहर पक्की बनेगी, क्योंकि यह कच्ची है, जिसके कारण तीस परसेन्ट पानी रास्ते में बेकार चला जाता है, मिट्टी पानी को सोख जाती है। उस समय इस पर 85 करोड़ रुपये लगने थे और मैंने तब पांच करोड़ रुपये दे दिये थे। लेकिन आज आठ साल के बाद दिल्ली की मुख्य मंत्री उसका उद्घाटन कर रही हैं और कह रही हैं कि तीन साल के बाद पानी आयेगा। मेरा कहना है कि पांच साल पहले जो समझौता हुआ, उसे क्यों नहीं लागू किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो दिल्ली में पानी का संकट है, वह इस सरकार के कारण है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दिल्ली में बिजली का भी संकट है। श्री चंद्रशेखर जी यहां नहीं हैं। आपको याद होगा मार्च महीने में मैंने यहां यह इशू उठाया था कि दिल्ली में साठ लाख लोग गरीब बस्तियों, झुग्गी-झोंपड़ियों और अनअर्थोराइज्ड कालोनियों में रहते हैं। उन्हें सिंगल प्वाइंट के नाम पर एक हजार कांट्रैक्टर्स बिजली सप्लाई करते हैं। बिजली सरकार की है और सरकारी खजाने में पैसा जमा नहीं होता है तथा जो बिल दिये जाते हैं, वे प्राइवेट बिल्स हैं और उन बिलों पर लिखा हुआ है - 50 रुपये रोजाना लेट फीस। साढ़े छः हजार रुपये डेवलपमेंट चार्ज लिये जा रहे हैं। लेकिन कालोनियां रेगुलराइज नहीं हुई हैं, उन्हें फिर से पैसा देना पड़ेगा। उस समय मैंने वे रसीदें दिखाई थीं, तब चंद्रशेखर जी ने कहा था। (व्यवधान)

श्री प्रवीण राट्रपाल (पाटन) : कुछ इलैक्शन के लिए भी बाकी रखो। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मैं वही कहना चाहता हूँ कि इलैक्शन के लिए जो एक हजार कांट्रैक्टर्स हैं। (व्यवधान)

श्री अवतार सिंह मडाना (मेरठ) : यह किसने किया। (व्यवधान) आज आपको इलैक्शन के कारण दिल्ली की याद आ रही है, यू.पी. में देखिये क्या हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : श्री चंद्रशेखर जी ने उस समय रसीदें देखकर कहा था कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में जैसे जंगल का राज है। उसका परिणाम क्या हुआ, बिजली जब सरकार के अंडर थी तो साल में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा कभी नहीं हुआ। लेकिन पिछले नौ महीनों में जब से दिल्ली में बिजली कंपनियों को दी गई हैं, साढ़े अठारह सौ करोड़ का घाटा नौ महीनों में हो गया है। अगले साल 3600 करोड़ का घाटा होने जा रहा है। बिजली कंपनियों के हाथ में बिजली देने के पहले साल में कभी एक हजार करोड़ से ज्यादा का घाटा नहीं हुआ था और अब बिजली की दरें भी बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सारे मामले की सी.बी.आई. से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से एक हजार कांट्रैक्टर्स दिल्ली को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं और उन्हें कोई रसीदें नहीं दी जा रही हैं। इस सबकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए।

MR. SPEAKER: On the same issue, I have received a notice from Shri Lal Bihari Tiwari. Shri Tiwari, your name will be associated with it. However, I will give you only one minute to speak.

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, श्री मदन लाल खुराना जी ने जो कहा है, मैं उसके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की डेढ़ करोड़ पापुलेशन में 40-50 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ियों, अनअर्थोराइज्ड कालोनियों और पुनर्वास बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने पीने के पानी की लाइन नहीं डाली है। वहां टैंकर भेजकर पानी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : सर, दिल्ली स्टेट का मीटर है, उसे यहां उठाने की आपने इजाजत दी है। (व्यवधान) अभी छः महीने चुनाव के रह गये हैं, इसलिए जबरदस्ती यह मामला यहां उठाने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: No State matter should be permitted.

श्री लाल बिहारी तिवारी : लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जो थोड़ा बहुत पानी लोगों को मिल रहा है, उससे बीमारियां फैल रही हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। लोगों की डिमांड पर टैंकर नहीं भेजे जा रहे हैं, लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। भाजपा सरकार के जमाने में सोनिया विहार में 140 एम.जी.डी. ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना बनी थी, लेकिन दो साल बीतने के बाद आज तक वह पूरी नहीं हुई है। पूर्वी दिल्ली को जरूरत के मुताबिक 200 एम.जी.डी. पानी मिलना चाहिए, लेकिन कुल 50 एम.जी.डी. पानी मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि दिल्ली में तुरंत पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, श्री मदन लाल खुराना जी और श्री तिवारी जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के डेढ़ करोड़ लोगों को पानी और बिजली नहीं मिल रही है। चारों तरफ भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उत्तर प्रदेश में देखिये बिजली और पानी का कैसा संकट है। (व्यवधान)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए और अगर वे इस्तीफा नहीं देती हैं तो वहां केन्द्र सरकार को दखल देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : उत्तर प्रदेश की बात करो। एक एक बूँद पानी के लिए उत्तर प्रदेश का नागरिक तरस रहा है। (व्यवधान) सबसे अच्छी सरकार दिल्ली में चल रही है। अब दो तिहाई बहुमत से जीतकर आएंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठ जाएं। रामजीलाल सुमन जी, आप अपना विाय रखें।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale's name will also be associated with this.

...(Interruptions)